लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 अक्तूबर 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक -28

“ जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले स्वयं में लाएं।

: महात्मा गांधी

पहला सुख निरोगी काया उत्सव तो फिर भी आते रहेंगे 3

औषधीय खेती इंद्रायण, फायदे का सौदा 4

पर्यटन का मुख्य आकर्षण बना टिक्कर ताल 6

पारदर्शिता का सूत्रधार ऑनलाइन कामकाज

मनोज प्रभाकर

डिजिटलाइजेशन ने भारत की तस्वीर बदलकर रख दी है। प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार ने इस तकनीक को हाथों-हाथ लिया और व्यवस्था में समायोजित कर दिया। सात साल के निरंतर प्रयास के बाद आज परिणाम सुखद हैं। इससे न केवल राजकीय कामकाज की चाल ढाल में बदलाव आया है, डावांडोल होती व्यवस्था भी पटरी पर लौटी है। आम आदमी को अपने छोटे मोटे कार्यों के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जाते भी हैं तो सुप्रबंधन के तहत कार्य कराते हैं। 'सेवा-पानी' शब्द परिसरों से गायब हो चुका है। 'सेवा का अधिकार' कानून लागू होने के बाद तो अफसरों व कर्मचारियों की आम जनता के कार्य के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी है।

वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने को हैं। इस समयावधि में गठबंधन सरकार ने प्रगति के कई आयाम स्थापित किए हैं। 'सबका साथ सबका विकास' की मूलधारा पर चलते हुए सभी नब्बे हलकों की प्रगति पर बराबर ध्यान दिया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से बेशक राजकोषीय व्यवस्था प्रभावित हुई, बावजूद इसके प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से चौतरफा विकास कार्य हो रहे हैं।

कुछ अर्से पहले तक जो लोग व्यवस्था से निराश होकर कहते थे कि 'कुछ नहीं होने वाला' वे अब कहने लगे हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सब मुमकिन है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल की कड़ी मेहनत व समर्पण भाव से जिस प्रकार राज्य में विकास कार्य हो रहे हैं वे वाकई भेदभाव से कोसों दूर हैं। इस सरकार में 'दुभात' नहीं है।

नौकरियों में पारदर्शिता आने से प्रदेश के युवाओं में चर्चा का ढंग बदला है। जिस चर्चा में पहले सिफारिश व मोलभाव का जिक्र होता था वह अब कितने नंबर का पेपर और किस प्रकार तैयारी होनी चाहिए का जिक्र होने लगा है। यानी छोरे छोरियों ने पढ़ने और पढ़ाना शुरू कर दिया है।

वर्तमान सरकार के जिस कार्य से लोगों का सबसे अधिक भरोसा जमा वह है 'ऑनलाइन कामकाज'। ऑनलाइन कामकाज से भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हुई है। इसमें और सुधार का प्रयास जारी है ताकि 'सुशासन' स्थाई तौर पर स्थापित हो सके।

तकनीकि दृष्टिकोण से सुशासन व्यवस्था का निर्वहन करने में वरिष्ठ अधिकारी राकेश गुप्ता का विशेष योगदान रहा। उनके कुशल निर्देशन में बखूबी कार्य हुआ। अब यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल संभाल रहे हैं। इनके निर्देशन में विभिन्न विभागों की 550 सेवाएं सरल सेवा केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं।

डा.अग्रवाल इस व्यवस्था को लेकर समय समय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सभी उपायुक्तों को कहा कि है वे रूटीन के कार्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य नागरिक सेवाओं जैसे सामाजिक मूल्यों से संबंधित योजनाओं पर अधिक ध्यान दें। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न योजनाओं में आईटी के प्रयोग की चहूं ओर प्रशंसा हो रही है। केन्द्र सरकार व कुछ अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया है। उन्होंने ई-आफिस के माध्यम से फाइलों को चलाने पर बल दिया।

परिवार पहचान पत्र के मामले में उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, इसलिए अधिकारी इस पर विशेष फोकस रखें। सरल केन्द्रों पर सिटीजन हेल्पलाईन न0 बदलकर 0172-3968400 होने पर इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए ताकि हर नागरिक इसका लाभ उठा सकें।

राज्य सरकार प्रदेश में अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को उसके घर-द्वार पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश है कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंदर काम करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने आईटी का उपयोग करते हुए नित नए-नए ऑनलाइन पोर्टल और सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, ताकि आमजन को सुगम और समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल सके।

मनोहरलाल मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू करने के बारे में डा. अग्रवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे में राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुहैया कराई जाए। आगामी नवम्बर माह में भारत सरकार द्वारा स्कूलों के मूल्यांकन से संबंधित जो परीक्षा ली जाएगी, उसका मॉक टेस्ट लेकर अभ्यास करवाया जाए ताकि प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल रैंकिंग आ सके।

राजनीति में भाग नहीं ले सकते सरकारी कर्मचारी

हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को लागू करते हुए राजनीति और चुनावों में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।

हरियाणा के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, हरियाणा के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सामान्य) को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 और 10 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर तत्काल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे किसी भी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने या सहायता करने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने का प्रयास करेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित कानून के अनुसार सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले हों और जहां एक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के सदस्य को ऐसे किसी भी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने या सहायता करने, या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने में असमर्थ है, तो वह इसकी रिपोर्ट सरकार को करेगा। किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति गत, अपने वाहन या निवास पर किसी चुनावी चिह्न का प्रदर्शन इस उप-नियम के अर्थ के तहत चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग माना जाएगा।

-संवाद ब्यूरो

परिवार पहचान पत्र से ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्राधिकरण की पहली बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक नवंबर, 2021 से विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के हकदार प्रत्येक पात्र परिवार के डेटा को सत्यापित किया जाए और जल्द से जल्द आवश्यक नियमों और नीतियों का प्रारूप तैयार करें ताकि लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो न केवल पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सभी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे हर परिवार को एक अलग परिवार आईडी मिलेगी, जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए मान्य होगी।

एचपीपीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता ने बताया कि अब तक 64 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 56 लाख से अधिक परिवारों ने हस्ताक्षर कर पंजीकृत डेटा पर सहमती दे दी है। डेटा का सत्यापन जारी है।

सरल पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही 315 सेवाओं में से 286 सेवाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही पीडीएस और पेंशन योजनाओं के डेटा को भी पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जबकि संपत्ति आईडी के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी।

पीपीपी डेटा एकत्र और सत्यापित करते समय सुरक्षा के उच्चतम मानक को अपनाया गया है और डेटा की चोरी या अन्य किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध की कोई संभावना नहीं है। इस डेटा की किसी भी तरह की चोरी से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष आईटी टीमों को लगाया गया है।

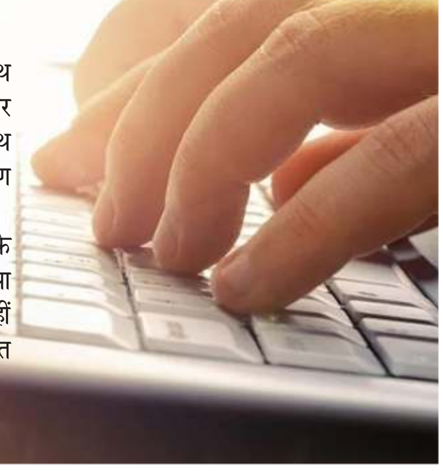

संपादकीय

नवरात्रों में बेटियों का महत्व

नवरात्रों में बेटियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नए प्रयासों की चर्चा कर लेनी प्रासंगिक होगी। हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की उन्नति के लिए निरंतर किये जा रहे प्रयासों की बदौलत आज प्रदेश में लड़कियां न केवल स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही हैं बल्कि उच्च व तकनीकी शिक्षा में भी आगे बढ़ रही हैं।

गर्व की बात है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा से 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। प्रति विद्यार्थी 50 हजार रुपए वार्षिक दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना और सक्षम छात्रवृत्ति योजना चलाई हैं। ये योजनाएं बेटियों और दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगी और उनके कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ही अनुरूप स्थानीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा के तकनीकी विद्यालयों में इस सत्र से इंजीनियरिंग के कोर्स हिन्दी भाषा में आरंभ किये जा रहे हैं।

वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में बेटियों और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। राज्य सरकार की योजनाएं हमेशा अंत्योदय दर्शन पर केंद्रित रही हैं। हरियाणा सरकार का यही प्रयास है कि पैसों के अभाव के कारण कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को प्रदान कर रही है। कोरोना के कारण निराश्रित हुई किशोरियों को 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत वित्तीय सहायता के तौर पर 1500 रुपए भी देने का प्रावधान किया है।

हरियाणा सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। दिव्यांगों के उत्थान और पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयास कर रही है ताकि यह वर्ग सामाजिकए आर्थिक, शैक्षणिक व शारीरिक रूप से समर्थ होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

- डा चंद्र त्रिखा

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा हिसार हवाई अड्डा

हरियाणा सरकार प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट 'महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हिसार' सहित प्रदेश की सभी छह हवाई पट्टियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर जनता को समर्पित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

इसी कड़ी में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उड्डयन विभाग, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पर्यावरण विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

हिसार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के काम में हो रही देरी के बारे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिसार-बरवाला रोड़ बंद होने से लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए मिर्जापुर रोड़ से तलवंडी के पास नेशनल हाइवे को जोड़ने वाला वैकल्पिक रोड़ का फाईनल-प्लॉन अधिशीघ्र तैयार करें ताकि रोड़ का निर्माण कार्य शुरू हो।

हवाई अड्डा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 33 केवी स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण 7200 हेक्टेयर में होने जा रहा है, ऐसे में इतने बड़े क्षेत्र हेतु जल निकासी के लिए अधिकारी अभी से मेगा ड्रैनेज प्लान तैयार करें जिससे आने वाले 50 वर्षों में भी जल निकासी की कोई समस्या न हो।

करनाल, पिंजौर, भिवानी, नारनौल, गुरूग्राम में हेलीपेड सहित हवाई पट्टियों के विस्तार, उनके आधुनिकीकरण, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, चारदीवारी, रनवे लाईट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रौल हैंगर आदि पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने हरियाणा के ज्यादा युवाओं को पायलट की ट्रेनिंग देने की योजना पर भी विस्तार से अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री चौटाला ने हवाई अड्डे के पास से गुजरने वाली हाई-टेंशन लाइन को शिफ्ट करने के अलावा इन हवाई अड्डों पर 24 घंटे निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, यहां पेयजल आपूर्ति करने, हवाई अड्डे की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए।

–संवाद ब्यूरो

पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने के लिए टोल फ्री नंबर

वर्ष 2014 से राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया गया है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने के लिए जानकारी देने हेतु राज्य सतर्कता ब्यूरो का एक टोल-फ्री नंबर 18001802022 शुरू किया गया है। इस नंबर पर अभ्यर्थी पेपर लीक की एवज में पैसे मांगने वालों की जानकारी दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि कभी भी पेपर लीक से जुड़ें लोगों ने उनसे संपर्क किया हो, जो उन्हें परीक्षा के प्रश्नपत्रों या उत्तर कुंजी को एडवांस में देने का दावा करते हैं, तो अभ्यार्थी इस टोल-फ्री नंबर पर ऐसे सभी लोगों की जानकारी तुरंत साझा करें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को पकड़ने में जनभागीदारी निश्चित रूप से अहम भूमिका निभा सकती है।

सलाहकार संपादक :	डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक :	मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम :	संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक :	सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन :	गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट :	विकास डांगी

24 खिलाड़ियों को सौंपे जूनियर कोच नियुक्ति पत्र

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि सरकार की खेल पोलिसी बहुत ही कारगर है। इसके तहत राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को ग्रुप ए से सी तक नौकरियां देने का प्रावधान है। खेल राज्य मंत्री ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 खिलाडियों को जूनियर कोच के नियुक्ति पत्र सौंपे।

खेल मंत्री ने कहा कि अच्छे खिलाड़ी तैयार करने में कोच की अहम भूमिका होती है। सभी कोच खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपना विजन बनाकर फोकस करें और प्रदेश में और अच्छे खिलाड़ी बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि कोच खिलाड़ियों के स्वप्नों को साकार करने के लिए अथक प्रयास करेंगे और अभिभावकों के साथ साथ सरकार की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे।

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ग्रुप ए, बी और सी सेवा नियम-2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग काडर बनाया गया है। इसके लिए 550 पद स्वीकृत करवाए गए हैं। खिलाडि़यों की ऊपरी आयु सीमा भी 50 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष की गई है। इन नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को शामिल किया गया है।

कौशल विकास मिशन द्वारा उम्मीदवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 'हुनर- हरियाणा, उद्यम, नौकरी और रोजगार' ऐप लॉन्च किया गया है। युवाओं को औद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक और प्रतियोगी कोर्सेस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

थानेसर हलका के गांव भिवानी खेडा की 11 एकड़ जमीन में पशु चिकित्सा एवं कालेज खोला जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर युवाओं को पशु चिकित्सा में वीएलडी डिप्लोमा करने का अवसर मिलेगा।

मनोज प्रभाकर

पहला सुख निरोगी काया

उत्सव तो फिर भी आते रहेंगे

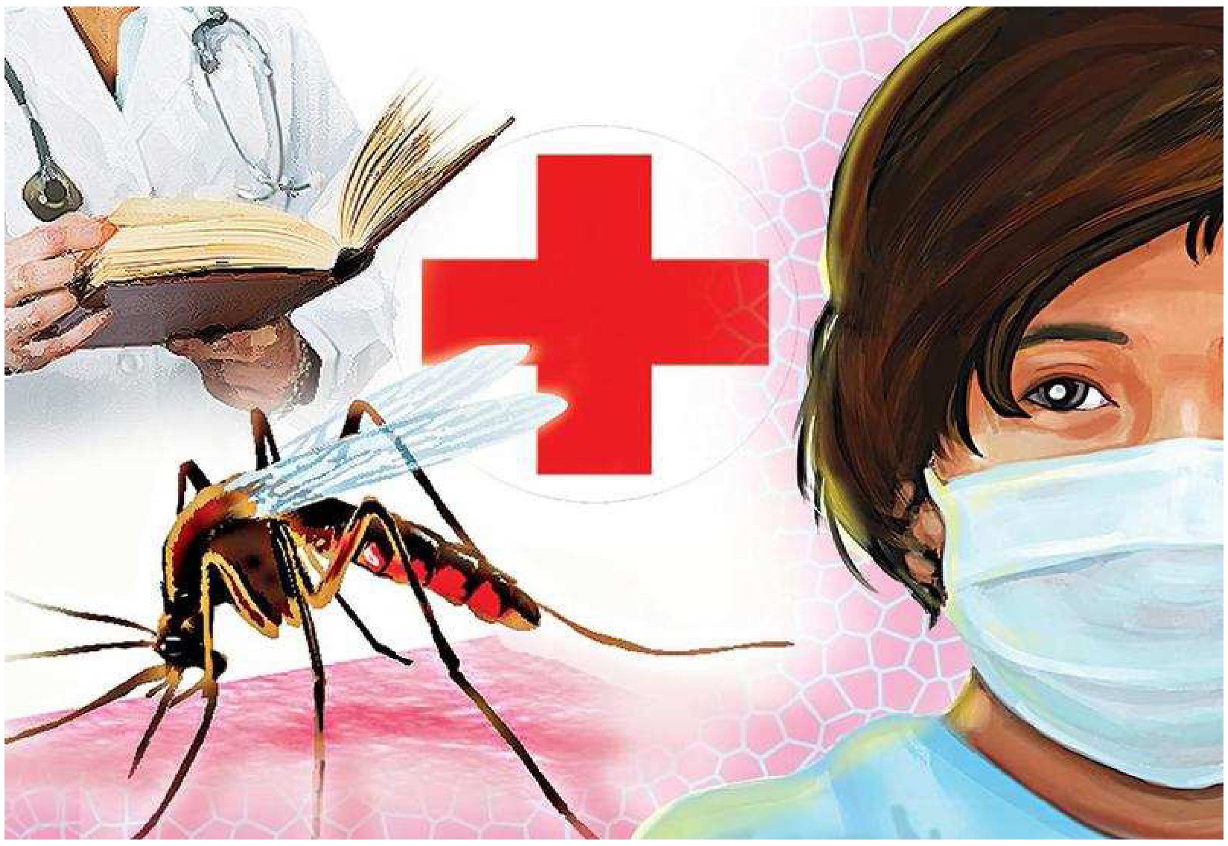

सर्द ऋतु ने दस्तक दे दी है। उत्सव की रंगत भी यौवन पर है। प्राकृतिक दृष्टि से इन दिनों में हर किसी की चाह खुलकर जीने की होती है। ऐसे में सेहत के प्रति लापरवाही स्वाभाविक हो जाती है। कुछ अर्से से वैश्विक महामारी का प्रभाव यथा है इसलिए हल्की लापरवाही भी परेशानी का सबब बन सकती है।

कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है और वायरल बुखार के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल यह वर्षा ऋतु के विदा होने का असर है जो हर वर्ष होता है। इस बार बरसात औसत से अधिक हुई है जिसकी वजह से प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में बरसात का पानी खड़ा है। खेतों की फसल प्रभावित हुई है तथा गांव व शहरों के बाहरी क्षेत्रों में कहीं ज्यादा तो कहीं कम पानी जमा है। इस खड़े पानी की वजह से मच्छरों का पनपना सहज है जिनकी वजह से रोग बढ़ सकते हैं।

बीते पखवाड़े से डेंगू के मरीजों की संख्या में उछाल देखा गया। अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक 989 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। इनके अलावा मलेरिया के 45 और चिकनगुनिया के पांच मरीज मिले हैं। फरीदाबाद में सर्वाधिक डेंगू के मरीज मिले हैं, इसके बाद गुरुग्राम, नूह, पंचकूला, सिरसा, अंबाला और कैथल में 50 से अधिक मरीज मिले हैं। झज्जर व पलवल में भी केस आए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है। वर्तमान में कुल 1410 हस्तचालित मशीन और 35 व्हीकल फागिंग मशीनों की मदद से फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है।

यहां पैदा होते हैं मच्छर

डेंगू पैदा करने वाले मच्छरों का लारवा साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। कूलर, ओवरहेड टैंक, प्लास्टिक बैग, खाली बोतलों के अलावा इधर उधर फेंके गए कचरे और छत पर फेंके गए सामान, फ्रिज के पीछे वाली ट्रे, पक्षियों के लिए रखे जाने वाले बर्तन और इधर उधर पड़े टायरों में जमा होने वाले पानी में यह मच्छर पनपते हैं।

डेंगू की मुफ्त जांच

मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने काफी इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 27 प्रयोगशालाओं में डेंगू की मुफ्त जांच की जा रही है। निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में भी डेंगू की जांच के लिए अधिकतम 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। निजी अस्पतालों के लिए डेंगू मरीजों की रिपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य होती है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था की गई है।

घर पर ही मनाएं उत्सव

तीज त्योहारों का समय है। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में अक्सर भीड़ रहती आई है, जिससे बचना होगा। मेले आयोजकों को भी सतर्कता बरतनी होगी। इन दिनों में प्रदेश में कई जगह मेले आयोजित होते हैं। राज्य सरकार की ओर से आम जनों को सलाह दी गई है कि वे मेलों में कम से कम जाएं और भीड़ से बचें। दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में रामलीलाओं का आयोजन होता है। उनमें भीड़ न होने दें। कोरोना से बचने के लिए तय किए गए मापदंडों का पालन करें। घर पर ही रहकर उत्सव बनाएं तो बेहतर होगा। घर से निकलें भी तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगा लें। दशहरे के बाद दीपावली पर भी बाजारों में अक्सर भीड़ देखी जाती है। कोरोना से जारी जंग के चलते उससे बचना होगा। लापरवाही की वजह से कोई उत्सव फीका न हो जाए इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। जान रहेगी तो पर्व फिर भी आते रहेंगे।

> **तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार**
>
> पहली उम्मीद तो यही है कि भविष्य में कोरोना का कोई केस न आए। बदलते मौसम की वजह से अगर ऐसा होता भी है तो राज्य स्तर पर कोरोना संक्रमण की आशंकित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन की ओर से जरूरी दवाइयां, उपकरण, बिस्तर, आक्सीजन आदि की पूरी तैयारी है।
>
> **अनिल विज, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा**

लोगों को लगाई वैक्सीन

राज्य में अभी तक कुल 2,36,95,387 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है जिनमें से 1,69,83,612 लोगों को पहली डोज़ और 67,11,775 लोगों को दूसरी डोज़ लगाई जा चुकी है। इसी तरह, 18 से 44 साल के 1,32,81,106 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है जबकि 45 से 60 साल की आयु वर्ग के 53,58,268 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 60 साल से अधिक आयु के 40,60,191 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 5,01,194 फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीनेट भी किया गया है तो वहीं 4,94,628 हेल्थकेयर वर्कर को वैक्सीनेट किया जा चुका है।

स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने राज्य के 14,386 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 24 लाख विद्यार्थियों के लिए 'फर्स्ट-एड बॉक्स' स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 'हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद' ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल करीब 3 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। विज्ञान के अध्यापक को 'फर्स्ट-एड' का प्रशिक्षण देकर प्रभारी बनाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल के लिए 2,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं।

एक स्कूली बच्चा अपना ज्यादा समय स्कूल में ही व्यतीत करता है। अगर इस दौरान बच्चे को कोई चोट लग जाती है तो तुरंत प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ती है। इसी को देखते हुए सरकार ने 'स्कूल स्तर पर बचाव व सुरक्षा के लिए फंड' योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए 2 करोड़ 87 लाख 72 हजार रूपए जारी किए हैं।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के 11,049 प्राइमरी व 3,337 सैकेंडरी स्कूलों में 'फर्स्ट-एड बॉक्स' की किट खरीदने के लिए बजट निर्धारित किया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक तथा जिला खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सूची में दर्शाए गए 24 आइटमों को 'फर्स्ट-एड बॉक्स' किट में रखें।

आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के आयाम

- सदैव ब्रह्ममुहूर्त (प्रातः 4-5 बजे) उठना चाहिए।
- बिस्तर से उठते ही मूत्र विसर्जन के पश्चात 2-3 गिलास गुनगुने पानी का सेवन करें। इससे सिरदर्द, अम्लपित्त, कब्ज, मोटापा, रक्तचाप, अपच सहित कई रोगों से बचाव होता है।
- स्नान सदा सामान्य शीतल जल से करना चाहिए, जहाँ निषेध न हो।
- सोने से पूर्व एवं भोजन के पश्चात् मूत्र त्याग अवश्य करना चाहिए। यह आदत आपको कमर दर्द, पथरी तथा मूत्र सम्बन्धी बीमारियों से बचाती है।
- सरसों, तिल या अन्य औषधीय तेल की मालिश नित्यप्रति करनी चाहिए।
- क्षमतानुसार प्रातः भ्रमण, योग, व्यायाम करना चाहिए।
- भोजन के 30 मिनट पहले तथा 30 मिनट बाद तक जल नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ जल नहीं पीना चाहिए।
- दिनभर में 3-4 लीटर जल थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहना चाहिए।
- भोजन के प्रारम्भ में मधुर-रस, मध्य में अम्ल, लवण रस (खट्टा, नमकीन) तथा अन्त में कटु, तिक्त, कषाय (तीखा, चटपटा, कसैला) रस के पदार्थों का सेवन किया जा सकता है।
- भोजन के उपरान्त वज्रासन में 5-10 मिनट बैठना तथा बांयी करवट 5-10 मिनट लेटना चाहिए।
- भोजन के तुरन्त बाद दौड़ना, तैरना, नहाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
- भोजन के तत्काल बाद सो जाने से पाचनशक्ति कमजोर हो जाती है।
- शरीर एवं मन को तरोताजा एवं क्रियाशील रखने के लिए औसतन 6-7 घन्टे की नींद आवश्यक है।
- दूध के साथ दही, नीबू, नमक, तिल, उड़द, जामुन, मूली, मछली, करेला आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
- रात्रि में सोने से पूर्व दांतों की सफाई, नेत्रों की सफाई एवं पैरों को शीतल जल से धोएं।
- रात्री में शयन से पूर्व किये गये कार्यों की समीक्षा कर अगले दिन की कार्य योजना बनानी चाहिए। तत्पश्चात् गहरी एवं लम्बी सहज श्वास लेकर शरीर एवं मन को शिथिल कर निद्रा में जाना चाहिए।

– डा. हरिपाल, बीएएमएस, एमडी

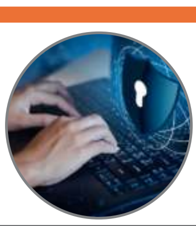

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में 'साइबर सिक्योरिटी अवेयरनैस' कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों, कर्मचारियों व समाज के अन्य लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके।

प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सर्वे, गिरदावरी तथा इमेजिंग के कार्य को तत्परता से निपटाने के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फोरमेशन सर्विस आफ हरियाणा लिमिटेड का गठन किया गया है।

औषधीय खेती इंद्रायण, फायदे का सौदा

संगीता शर्मा

महेंद्रगढ़ डेरोली जाट गांव के ऋषिपाल किसानों को इंद्रायण की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रयोग के तौर पर उन्होंने मीठी तुलसी की खेती की है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के जरिए ऋषि पाल इंद्रायण व मीठी तुलसी के उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

आयुर्वेदा की पढ़ाई कर चुके ऋषिपाल ने बताया कि महेंद्रगढ़ के जोनावास गांव के किसान शिवकांत को आधा एकड़ ज़मीन में कांट्रेक्ट खेती के माध्यम से इंद्रायण बीज की खेती करवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 20,000 रुपए किसान को दिए हैं। ज़मीन बालू है व खाली पड़ी थी और उन्होंने इसमें प्रयोग के तौर पर इंद्रायण की बिजाई की है। इस फसल में पानी की ज़रूरत नहीं होती है और तीन महीने की फसल तैयार हो जाती है। इसकी जड़ बहुत लंबी होती है और एक बार लगाने के बाद दोबारा बारिश में इसका फुटाव हो जाता है। इसकी जड़, पत्ते व फूल सभी स्वास्थ्य के हिसाब के बेहद लाभप्रद होते हैं।

उन्होंने इंद्रायण यानी गरमुंडा फल से शुगर की दवाई बनाई जोकि पूर्ण रूप से सफल रही। आज वे खेत में ही डायबिटीज केयर जूस बनाते हैं और शुगर के मरीजों के लिए यह जूस लाभप्रद है। डायबिटीज केयर जूस के साथ-साथ पेट के लिए चूर्ण भी तैयार करते हैं। कोरोना काल के दौरान एक एकड़ ज़मीन ठेके पर लेकर मीठी तुलसी की खेती शुरू की थी। वह मीठी तुसली का पाउडर, मीठी तुलसी के सूखे पत्ते, मीठी तुलसी के अर्क, कामसुधा गोखरू चूर्ण, इंद्रायाण पाउडर और इंद्रायण का तेल ऋषि हर्बल आयुर्वेदा द्वारा तैयार किया जाता है।

स्वास्थ्यवर्धक है इंद्रायण

बताया कि राजस्थान के बाडमेर व जोधपुर में इंद्रायण की खेती हो रही है और इस खेती से किसान अच्छा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ में नांगल काठा गांव के पास दोहान नदी है जहां पर इंद्रायण लगे हुए हैं। यह जंगलों में अपने आप उग जाते हैं। वह दो पिक अप गाड़ी वहां से इंद्रायण लेकर आए जिसमें एक पिकअप में 60-60 क्विंटल फल आया था। इस फल के बीज निकालकर उन्होंने देसी तकनीक से तेल तैयार किया है। उनका कहना है कि हमारे आस-पास कई ऐसे चीजें उगी होती है, जिसका स्वास्थ्य को अधिक लाभ पहुंचाता है। मगर लोगों का उस ओर ध्यान नहीं होता। मैंने बेकार में उगे इंद्रायण का उपयोग करके स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद तैयार किये हैं। वह इंद्रायण का जूस, कैंडी, चूर्ण और साबुन बनाकर बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके ग्राहक अलग-अलग राज्यों व जिलों से हैं, जिन्हें वह पार्सल करके प्रोडेक्ट भेजते हैं। हरियाणा सरकार लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को अधिक बढ़ावा दे रही है, इसलिए युवाओं को नौकरी की बजाय खेती में भी रोज़गार का प्रयास करना चाहिए।

आयुर्वेद में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए इन्द्रायन का उपयोग किया जाता है। यह एक बारहमासी वेल होती है। इन्द्रायन में मौजूद पोषक तत्व विभिन्न प्रकार से हमारी मदद करते हैं। इससे प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभों में घावों को ठीक करना, मधुमेह, मुंहासों का उपचार, कब्ज का इलाज, बवासीर, जोड़ों का दर्द आदि शामिल है।

अन्य लाभ

» जिन लोगों को कब्ज की समस्याएं है उनके लिए इंद्रायण बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। इस पौधे से प्राप्त फल का उपयोग कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

» औषधीय गुणों से भरपूर इंद्रायण के फ़ायदे बवासीर से छुटकारा दिलाने मे मदद कर सकते हैं। इसके लिए पिप्पली और इन्द्रायण की जड़ों को पीसकर गोलियां तैयार कर लें। इन गोलियों को सूरज की रोशनी में सुखा लें। इन गोलियों को नियमित रूप से प्रतिदिन पानी के साथ सेवन करें। यह बवासीर के प्रभावी और प्राकृतिक इलाजों में से एक है।

» कड़वा सेब ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। इंद्रायण की जड़ों से निकले रस का सेवन कर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस और गठिया जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।

सरसों की बीजाई का समय

किसानों ने सरसों फसल की बिजाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 12 के करीब ऐसे जिले हैं जहां किसान सरसों की बिजाई करते हैं। दक्षिण हरियाणा के किसानों की यह फसल रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।

कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि सरसों की आरएच 725 किस्म किसानों के लिए काफी लाभदायक है। यह किस्म वर्ष 2018 में समस्त हरियाणा के लिए अनुमोदित की गई थी। इस किस्म की खास बात यह हैं की यह 136-143 दिन में पक कर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 25 से 27 मण प्रति एकड़ है। इसका दाना सुडोल व पत्तियां लंबी व तेल की मात्रा 40 प्रतिशत है। यह वर्तमान समय की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। आरएच 749 किस्म की फसल 145 से 148 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं की इसकी उंचाई मध्यम व तेल की मात्रा 39-40 प्रतिशत है। इसकी पैदावार 25 से 28 मण प्रति एकड़ आंकी गई है।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आरएच 8812 किस्म जिसे लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह किस्म अधिक उपज देने वाली किस्मों की श्रेणी में आती है। इसकी फलियां मोटी व बीज काले रंग के होते हैं। इस किस्म की औसत पैदावार 25 मण प्रति एकड़ मापी गई है। यह किस्म 142 से 145 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा 39 से 40 प्रतिशत है।

सरसों की फसल के लिए किसानों को बीज के अच्छे अंकुरण के लिए खेत को पहले अच्छी प्रकार से पहले तैयार करना चाहिये। हैरो व कल्टीवेटर से खेत की पहले जुताई करें उसके बाद सुहागे से मिट्टी को समतल करें। सरसों की विभिन्न किस्मों के लिए अक्तूबर माह माना गया है।

महेंद्रगढ़ से कृषि अधिकारी योगेश यादव के अनुसार सभी तेल वाली फसलों को गंधक की आवश्यकता होती है। गंधक के श्रोत के रूप में किसान प्रति एकड़ 2 बैग जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 10 किलो जिंक सल्फेट को ओर 14 किलोग्राम मयुरेट को खाद बिजाई से पहले खेत में एक समान बिखेर देना जरूरी है। इसके बाद 30 किलोग्राम डीएपी और 25 किलोग्राम यूरिया को मशीन द्वारा ड्रिल करने से फसल बेहतर होती है।

-संवाद ब्यूरो

भावांतर भरपाई योजना में शामिल हुआ बाजरा

प्रदेश सरकार ने बाजरे की उपज को भी 'भावांतर भरपाई योजना' में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इससे पहले, हरियाणा में बागवानी फसलों के लिए भी 'भावांतर भरपाई योजना' लागू की जा चुकी है। इस योजना में 21 बागवानी फसलें हैं।

» बाजरे के औसत बाजार भाव व एम.एस.पी. के अंतर को भावांतर मानते हुए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल के सत्यापन उपरांत सही पाये गये किसानों को औसतन उपज पर 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा।

» बाजरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

» खरीफ -सीजन 2021 में बाजरे के लिए 2 लाख 71 हजार किसानों ने 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। इसमें से लगभग 8 लाख 65 हजार एकड़ भूमि का सत्यापन हुआ है। खरीद शुरू होते ही किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 600 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर औसत उपज के अनुसार भुगतान कर दिया जाएगा। यह भुगतान 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर सत्यापित किसानों को ही किया जाएगा।

» इसके अलावा, राज्य सरकार पहली बार अरहर, उड़द और तिल की खरीद भी करने जा रही है जो एक दिसंबर से शुरू होगी।

» किसानों को बाजरे के स्थान पर तिलहन और दलहन जैसे कि मूंग, अरहर, अरंडी, मूंगफली जैसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाजरे के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की बिजाई करने और कुल बाजरे का उत्पादन कम करने वाले किसानों को ही 4,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।

» प्रदेश में बाजरे की खरीद के लिए 86, मूंग की खरीद के लिए 38, मक्का के लिए 19 तथा मूंगफली की खरीद के लिए 7 खरीद केंद्र बनाये गये हैं। धान की खरीद के लिए भी 199 खरीद केंद्र बनाये गये हैं।

पशुपालन बना रोज़गार

हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोतरी करने तथा डेयरी व्यवसाय से बेरोज़गार नवयुवकों को स्वरोज़गारपरक बनाने के उद्देश्य से दुग्ध एवं डेयरी से संबंधित कईं नई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं। विभाग द्वारा 4 व 10 दुधारू पशुओं (भैंस/गाय) की डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार, 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति से जुड़े व्यक्तियों के लिए 2/3 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने तथा सूअर पालन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। भेड़ या बकरियों की डेयरी करने वाले व्यक्तियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

ऐसे उठाएं लाभ

डेयरी पालन का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करते समय परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चैक तथा बैंक की एनओसी अपलोड करनी होगी। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में विभाग के निकटतम कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

रोजगार विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए इच्छुक युवा ग्रेडअप पोर्टल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।

सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2021 को गुरुग्राम में राज्य स्तरीय 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

सहकारी चीनी मिलों में पिराई की तैयारी

एथेनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे व आलू में पाए जाने वाले ग्लूकोज पर होगा अध्ययन

राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों में अक्तूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान पिराई सत्र चालू कर दिया जाएगा ताकि गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़ें।

सहकारिता विभाग के मुताबिक पलवल की सहकारी चीनी मिल को आगामी 26 अक्तूबर, पानीपत-करनाल-शाहाबाद की सहकारी चीनी मिलों को आगामी 9 नवंबर, रोहतक की सहकारी चीनी मिल को 10 नवंबर, सोनीपत-जींद-महम-गोहाना की सहकारी चीनी मिलों को 11 नवंबर और कैथल सहकारी चीनी मिल तथा असंध की चीनी मिल को आगामी 12 नवंबर को गन्ना पिराई के लिए चालू कर दिया जाएगा। संबंधित चीनी मिलों के संबंधित अधिकारियों को समय रहते अपनी चीनी मिल की मरम्मत व रख-रखाव का कार्य पूरा कर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसानों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।

पानीपत चीनी मिल जनवरी में शुरू होने की संभावना

पानीपत की नई चीनी मिल को शहर से बाहर निकाला गया है। आने वाले जनवरी, 2022 के प्रथम सप्ताह के दौरान पानीपत की सहकारी चीनी के नए संयंत्र के चालू होने की संभावना है। अधिकारियों को कहा गया है कि पहली जनवरी, 2022 तक नए संयंत्र को चालू करने के संबंध में सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। गौरतलब है कि पानीपत की सहकारी चीनी मिल में को-जनरेशन के लिए 132 केवी लाईन के मामले को एचवीपीएनएल तथा एचईआरसी के साथ समन्वय किया जा रहा हैं। इसी प्रकार, करनाल की सहकारी चीनी मिल में 132 केवीए लाईन की योजना है।

बाजरे व आलू में ऐथनॉल की तलाश

एथेनॉल के उत्पादन में गलूकोज का महत्व होता है। इस पर सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि एथोनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे व आलू में पाए जाने वाले गलूकोज के बारे में अध्ययन किया जाए कि बाजरे व आलू में पाए जाने वाले ग्लूकोज से एथेनॉल का उत्पादन संभव हैं या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि आगामी 31 अक्तूबर तक शाहाबाद में 60 केएलपीडी के एथोनॉल परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, पलवल, सोनीपत, कैथल, जींद, गोहाना, महम, पानीपत, रोहतक व असंध की चीनी मिलों की क्षमता प्रगति इत्यादि की समीक्षा की गई।

निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश

सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइमलाईन फिक्स करें और यदि कोई भी थर्ड पार्टी समय पर कार्य करके नहीं दे रही है तो उस पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी से काम करवाएं ताकि समय की बचत हो सकें और परियोजना को समय पर शुरू किया जा सकें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य आधारित कार्य को आगे बढाते हुए समय अवधि को निर्धारित करें। परियोजना के मूल्यांकन के साथ-साथ चार्ट बनाकर सामानंतर गतिविधियों को भी अंजाम दें। उन्होंने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पारदर्शी तरीके से चलना आवश्यक है, यदि परियोजना में देरी हो रही है तो उन सभी बिंदूओं के जरिए जिम्मेदारी तय करें। **-संवाद ब्यूरो**

गुलदावरी व लिलियम के फूलों से महका जीवन

सोनीपत के गांव बड़खालसा के रविंद्र 9 एकड़ में फूलों की खेती करते हैं। रविंद्र ने किसान होने के साथ-साथ राजनीतिक शास्त्र से स्नातकोत्तर भी किया हुआ है। वे फूलों की खेती में खर्च निकाल कर सालाना 60 लाख रूपये से ज्यादा की कमाई करते हैं। वे उन किसानों का भी मार्ग दर्शन भी करते हैं जो इस क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे पिछले 26 वर्ष में 150 से ज्यादा किसानों का फूलों की खेती के बारे में मार्ग दर्शन कर चुके हैं। ये किसान किसी एक गांव के ना होकर हरियाणा भर के विभिन्न जिलों के हैं। राज्य सरकार ने उन्हे वर्ष 2014-15 व 2019 में कृषि रत्न, पुष्प रत्न जैसे अवार्डो से सम्मानित भी किया है।

रविन्द्र ने बताया कि प्रारंभ से ही उनका जोर फसल विविधिकरण पर रहा है। उन्होंने 1995 से फसल विविधीकरण को अपनाकर फूलों की खेती करना प्रारंभ किया व बुलंदियों को छुआ। खास बात यह है की उन्होंने इस आधुनिक दौर में फूलों की खेती में बेहतर उत्पादन करके जहां अपनी लगन व मेहनत का परिचय दिया वहीं खेती को घाटे का सौदा मानने वाले लोगों को गलत साबित भी कर दिखाया। रविंद्र कहते हैं कि वे लिलियम और गुलदावरी के फूल लगाते हैं।

रविन्द्र ने बताया की बाजार में इन दोनों किस्मों को अच्छे दाम मिल जाते है। उनके अनुसार बाजार में 10 रुपए से 12 रुपए तक का लिलियम व 25 रुपए की गुलदावरी के फूलों की स्टिक बिकती है। आसपास कोई मंडी ना होने की स्थिति में तैयार माल को गाजीपुर मंडी में बिक्री के लिए ले जाते हैं। मंडी तक पहुंचने में 7 घंटे का समय लगता है। उन्होंने बताया कि वे गुलदावरी की पौध वो स्वयं तैयार करते हैं जबकि लिलियम के लिये उन्हे विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

नवरात्रों के दौरान अक्टूबर के महीने में उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। फरवरी-मार्च तक फूलों का पीक रहता है। इन महीनों में 40 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। फूलों को तैयार करने के लिए 10 से 12 बार पानी की सिंचाई करना जरूरी होता है। वे फूलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन करते हैं। ज्यादा पानी से फूल खराब भी हो जाते हैं। दोनों किस्मों के फूलों को पाली हाउस व नेट हाउस में तैयार करते हैं। जब उन्होंने फूलों का कार्य प्रारंभ किया तो बागवानी विभाग से पॉली हाउस व नेट के लिए 65 प्रतिशत सब्सिडी मिली थी।

उनके अनुसार जब वे बल्ब पोलैंड की कंपनियों से मंगवाते हैं तो वहां की सरकार भी किसानों को फाइटो सर्टिफिकेट देती है। यह सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है, जब बीजों में किसी प्रकार की बीमारी दिखाई नहीं पड़ती हो व फसल अच्छी लगती हो।

-सुरेन्द्र सिंह मलिक

मछली पालन

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी दलाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला से मुलाकात कर प्रदेश में दुग्ध, पशुपालन व मछली पालन के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में जानकारी दी और प्रदेश में इस क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं के बारे में बताते हुए विकास योजनाओं के लिए मांग रखी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी प्रोजेक्ट्स पर सामान्य जाति के प्रार्थियों को 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति व महिला प्रार्थियों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। जे.पी दलाल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हरियाणा प्रदेश में केंद्र की इस योजना को जोर-शोर से लागू किया गया है। प्रदेश में झींगा मछली पालन का जहां वर्ष 2014 में केवल 28 हैक्टेयर भूमि तक सीमित था, वहीं अब 493 हैक्टेयर भूमि में मछली पालन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 तक इसे 4 हजार हैक्टेयर भूमि तक किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कृषि के अनुपयोगी सिद्ध हुई भूमि को मछली पालन के लिए किसानों को लीज पर दी जाएगी। संवाद ब्यूरो

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देगी सरकार

कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री क्षेत्र से जुड़े विभिन्न उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

ONE DISTRICT ONE PRODUCT
एक जिला एक उत्पाद

प्रदेश के सभी 22 जिलों को 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' योजना के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है। योजना में सभी 22 जिलों का कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री आदि क्षेत्र से संबंधित अपना उत्पाद शामिल किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक और तकनीकी सहायता करके बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में वहां होने वाली फसलों, कृषि आदि के आधार पर उत्पादों का चयन किया है ताकि किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों को पूरा लाभ मिले और प्रदेश में कृषि निर्यात भी बढ़े।

स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पादों की प्रकृति के मुताबिक अंबाला जिले में प्याज, भिवानी-फतेहाबाद-महेंद्रगढ़ में मौसमी, नींबू, संतरा आदि खट्टे फल, दादरी-रोहतक-फरीदाबाद में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू, तरबूज आदि कुकुरबिट्स से संबंधित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

गुरुग्राम जिले में आंवला, झज्जर में अमरूद, जींद में मुर्गीपालन, करनाल मे हरी पत्तेदार सब्जियां, कुरुक्षेत्र में आलू, नूह-पलवल में टमाटर, पंचकुला में अदरक, हिसार-कैथल में दूध व दूध उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। इसी तरह सरकार द्वारा पानीपत जिले में गाजर, रेवाड़ी में सरसों, सिरसा में किन्नू, सोनीपत में मटर और यमुनानगर में आम से संबंधित उत्पादों को नई पहचान दिलाई जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' योजना बड़ा कदम है। राज्य सरकार इस तरह की लाभकारी योजना को केवल जिलों तक सीमित नहीं रखेगी और सरकार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसे सभी ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार हर ब्लॉक को उसके अपने उत्पाद के साथ एक औद्योगिक विजन से जोड़ेगी। बताया कि इसके लिए सरकार 'वन ब्लॉक वन प्रोडेक्ट' की योजना पर बहुत तेजी से कार्य कर रही है। इससे सभी ब्लॉकों में अलग-अलग उत्पादों के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

-संवाद ब्यूरो

महेंद्रगढ़-नारनौल स्टेट हाईवे पर गांव लहरोदा से शहरपुर नूनी सलूनी होते हुए गांव गुवानी तक 384 लाख रुपए की लागत से 18 फुट चौड़ी सड़क बनेगी। मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

करनाल में काछवा पुल से कैथल मार्ग पुल के बीच जेएनएल कैनाल व भाखड़ा कैनाल के बीच मनोरंजन पार्क बनाया जा रहा है। इस पर करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च आने का अनुमान है।

पर्यटन का मुख्य आकर्षण बना टिक्कर ताल

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकूला को पर्यटन की दृष्टि से एक नया केंद्र बनाने की परिकल्पना के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी के टिक्कर ताल में विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया है।

मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में विभिन्न एयरो और वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं। इन गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग द्वारा स्थानीय युवाओं को इन गतिविधियों से संबंधित कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन के विकास के लिए हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

देश और दुनिया भर में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का भी शुभारंभ किया। इससे पर्यटकों को होम स्टे के रूप में होटलों का एक शानदार विकल्प मिल सकेगा, जिससे उन्हें स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रहने और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों का अनुभव मिल सकेगा। प्रदेश में फार्म टूरिज्म को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, जहां अधिक से अधिक शानदार फार्मों को सूची में जोड़ा गया है। अब पर्यटक छुट्टियों का आनंद लेने के लिए अपने पसंदीदा फार्म हाउस का चुनाव कर सकते हैं।

मोरनी का विकास

मनोहर लाल ने टिक्कर ताल और मोरनी के साथ अपनी पुरानी यादों को स्मरण करते हुए कहा कि वर्ष 1990 में मैं यहां पार्टी के कामों के लिए आया करता था और एक बार मुझे मांधना गांव के स्कूल में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का अवसर भी मिला। उस समय महसूस हुआ कि यह क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा रहा है। तब हमने इस क्षेत्र को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन के मामले में विकसित करने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि मोरनी का विकास एकीकृत पंचकूला विकास योजना की एक प्रमुख विशेषता है। इसलिए 20 जून, 2021 को शुरू की गई सभी वॉटर और एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के निरीक्षण के लिए टिक्कर ताल का दौरा किया था।

एक नया अध्याय

आज के समय में जब पर्यटन उद्योग लगातार विकसित हो रहा है, हरियाणा पर्यटकों और आगंतुकों के लिए साहसिक खेलों के माध्यम से मौज-मस्ती व रोमांच के लिए एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। एडवेंचर स्पार्ट्स पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे अक्सर पर्यटन स्थलों का एक बेंचमार्क माना जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न साहसिक गतिविधियों का शुभारंभ पर्यटन उद्योग को लगातार विकसित करने व बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक कदम साबित होगा।

स्थानीय व्यंजनों का अनुभव

होम स्टे पॉलिसी के शुभारंभ के साथ ही स्थानीय निवासी अब पर्यटकों और आगंतुकों को व्यावसायिक आधार पर उचित मूल्यों पर अपने घर को रहने के लिए दे सकते हैं। जिन गृह मालिकों के घरों में अतिरिक्त कमरे हैं, वे पर्यटकों को खाने-पीने की सुविधा के साथ निर्धारित दरों पर दे सकते हैं। इस प्रकार, पर्यटकों को होटलों के व्यावसायिक वातावरण के बजाय स्थानीय रीति-रिवाजों, व्यंजनों आदि के अनुभव के साथ रहने के लिए स्वच्छ और सस्ती जगह उपलब्ध होगी।

होम स्टे योजना से बढ़ेगा रोज़गार

होम स्टे योजना का उद्देश्य पर्यटकों के लिए आवास के अधिक विकल्प बनाने के साथ-साथ इसके मूल्य को कम करके बाज़ार का विस्तार करना है। यह योजना बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के लिए पर्यटन के लाभों के विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा देगी जिनके पास इस तरह के उपयोग के लिए संपत्ति उपलब्ध है। यह योजना विभिन्न स्थानों पर और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर आवास विकल्पों की अधिकता प्रदान करेगी। जो पर्यटक लंबे समय तक यहां रुकने के इच्छुक हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस नीति के शुभारंभ के साथ ही पर्यटकों को निश्चित रूप से स्थानीय सामुदायिक जीवन का अनुभव मिलेगा जहां वे लोक गीतों का अनुभव व आस-पास के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा, ट्रेकिंग, मिट्टी के बर्तन बनाने, भोजन, नृत्य, कला और शिल्प आदि से परिचित हो सकते हैं। कौशल विकास मिशन के तहत पात्र चयनित होम-स्टे मालिकों को हरियाणा पर्यटन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

फार्म पर्यटन नीति में बदलाव

दैनिक जीवन की नीरसता को छोड़कर, फार्म टूरिज्म पर्यटकों व आगंतुकों को साधारण ग्रामीण जीवन से जुड़ने और उसका आनंद लेने की दिशा में पहला कदम है। संशोधित फार्म पर्यटन नीति में फार्म मालिकों और पर्यटकों दोनों के लिए अधिक विकल्पों और सुविधाओं को समाहित किया है। फार्म मालिक अब नीति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ अपने व्यवसाय को बड़े और लचीले वाणिज्यिक स्तर पर विस्तार कर सकते हैं। दूसरी ओर पर्यटक अब सुरक्षा के साथ वास्तविक ग्रामीण जीवन का आनंद ले सकते हैं। यह ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा और हरियाणा को पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में अलग पहचान स्थापित करने में लाभदायक सिद्ध होगा।

-संवाद ब्यूरो

पर्वतारोहियों को इनाम देने की योजना

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूल विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना बनाई जाएगी। इसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करेगा उसे 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। स्कूल विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 75 विद्यार्थियों व अध्यापकों का दल स्कूल शिक्षा विभाग एवं नेशनल एडवेंचर क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में 6111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट यूनम पर पर्वतारोहण करने जा रहा है।

हरियाणा देश का पहला राज्य है जो स्पोर्टस हब के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी ओलम्पिक एवं पैरालम्पिक में सबसे ज्यादा मैडल लाए हैं। इसलिए स्पोर्टस की तर्ज पर पर्वतारोहण करने वालों के लिए भी योजना बनाई जाएगी।

अब तक 64 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 56 लाख से अधिक परिवारों ने हस्ताक्षर कर पंजीकृत डेटा की सहमति दे दी है।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद सूरजकुंड मार्ग स्थित सूरजकुंड गोल चक्कर पर 307.23 लाख रुपए की लागत से बनाए गए ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस फुट ओवरब्रिज की काफी समय से मांग की जा रही थी।

‘सरस्वती’ का जानेंगे परत दर परत इतिहास

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग वर्ष 2022 तक सौंपेगा सर्वे रिपोर्ट

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की धरा से बहने वाली प्राचीन एवं पवित्र सरस्वती नदी के परत दर परत इतिहास का सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग सहित देश के जाने माने भू वैज्ञानिक करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट वर्ष 2022 तक सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के बाद सरस्वती नदी के पहलुओं का खुलासा हो पाएगा।

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के तत्वाधान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सरस्वती एक्सीलेंट रिर्सच सेंटर के सभागार मे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, इसरो व ऑन लाइन प्रणाली से जुडे वैज्ञानिकों की बैठक हुई जिसमें विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ।

विकास बोर्ड की ओर से उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की प्रोजेक्ट निदेशक डा. दिपाली कपूर, सीनियर वैज्ञानिक मनोज शुक्ला, सीनियर वैज्ञानिक हर्ष तिवारी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सरस्वती एक्सीलेंस शोध केन्द्र के निदेशक डा. एआर चौधरी, ऑन लाइन प्रणाली से जुडे इसरो के पूर्व महाप्रबंधक जेआर शर्मा, उपनिदेशक बीके बांदरा, इसरो के सेवानिृवत निदेशक एके गुप्ता, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के शोध अधिकारी डा. दीपा व जीएस गौतम उपस्थित हुए जिन्होंने सर्वे के बारे में तकनीकी रूप व वैज्ञानिक दृष्टि से खुलकर चर्चा की।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार की ओर से प्राचीन सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर प्रवाहित करने के प्रयास किए जा रहे है। इस नदी को प्रवाहित करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, इसरो व देश के जाने माने भूवैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।

यह वैज्ञानिक हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों में सरस्वती नदी के उदगम स्थल से लेकर गुजरात तक के पूरे चैनल का सर्वे करेंगे और इन राज्यों में यह तलाश किया जाएगा कि अभी भी धरती के नीचे किस-किस जगहों पर पानी के चैनल है और इन चैनल की उत्पत्ति और अभी तक धरती के नीचे बहने के क्या संस्थान रहे है। इसके साथ ही मिट्टी की परत दर परत पर भी शोध किया जाएगा कि किस तह पर सरस्वती नदी प्रवाहित होने के साक्ष्य रहे है और इस पवित्र नदी की गहराई कितनी रही होगी।

वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट में पवित्र सरस्वती नदी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2022 तक सौंपा जाएगा। इस कार्य को करने के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच वर्ष 2018 में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। सर्वे रिपोर्ट के बाद सबसे प्राचीन एवं पवित्र सरस्वती नदी के इतिहास के बारे मे जानकारी मिलेगी और इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय भी जुडेगा। इन शोध कार्यों से देश की युवा पीढ़ी को सरस्वती नदी के एतिहासिक पहलुओं से आत्मसात करने का अवसर भी मिलेगा।

-संवाद ब्यूरो

अब हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई

मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा का अपना अलग महत्त्व होता है। कई बार बच्चे अंग्रेजी में अधिक निपुण नहीं होते और हिंदी में व्यावसायिक व तकनीकी कोर्स करना चाहते हैं, मगर इसके आड़े अंग्रेजी भाषा आती है। जिसके चलते वह अपना पसंदीदा कोर्स नहीं ले जाते। युवाओं की इस समस्या का समाधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत किया गया है। एनईपी के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में भी इसको अपनाया जा रहा है। इस पहल पर कदमताल मिलाते हुए हरियाणा के तीन तकनीकी विश्वविद्यालयों में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स क्षेत्रीय भाषा (हिंदी) में इस सत्र से आंरभ किया जा रहा है।

तीन विश्वविद्यालय में हिंदी में कोर्स

हरियाणा में इन तीनों कोर्स में अतिरिक्त 30-30 सीटों को शुरुआत में रखा गया है तथा ये कोर्स दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (मुरथल) सोनीपत, जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाईएमसीए, फरीदाबाद और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार में शुरु होंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सभी निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की बैठक आयोजित करेगा और उन्हें उपरोक्त विषयों में अतिरिक्त सीटों के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस बैठक में एआईसीटीई के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ छात्रों को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। सरकार ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का विजन देशवासियों के सामने रखा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस शिक्षा नीति में पूरे सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन की अवधारणा की गई है। इसके तहत थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पर जोर दिया गया है। इससे शिक्षा को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी बनाया जा सकेगा तथा देश का युवा स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनेगा।

कंवरपाल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा

तकनीकी कोर्स क्षेत्रीय भाषा में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता को मॉनिटर करने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड का आरंभ किया जाएगा। इस डैशबोर्ड के माध्यम से इस पॉलिसी के कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। इस योजना के माध्यम से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को लागू करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 181 कार्यों की पहचान की गई है। जिनको शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूरा किया जाना है। इन कार्यों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट ऑप्शन, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश एवं निकासी की सुविधा, क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि शामिल है।

क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब शिक्षकों को पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना का प्रयास किया जाएगा और यदि पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में बच्चों और शिक्षक के बीच बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा। कक्षा एक से बच्चों को दो से तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी।

इस नीति के अंतर्गत यदि दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों की कमी है। इस स्थिति में विशेष तौर से प्रयास किए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों को भर्ती की जाएगी। जिसके अंतर्गत रिटायर हुए शिक्षकों को भी दोबारा से बुलाया जा सकता है।

माध्यमिक विद्यालय में बच्चे अपने पसंद की विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीस, जैपनीज आदि होंगी। यह सभी प्रयास भारत की शिक्षा को वैश्विक तौर पर पहचान बनाने का एक प्रयास है।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के प्रयास

- हरियाणा में न केवल पर्याप्त स्कूल कॉलेज हैं, बल्कि विभिन्न विषयों की विशेषज्ञता से युक्त विश्वविद्यालय व विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान भी हैं ।
- राज्य में हर विद्यार्थी के घर से 2 से 3 किलोमीटर दूरी के भीतर एक स्कूल अवश्य है। इसी प्रकार, हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज उपलब्ध है।
- नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफ़ी आगे है। हमारे यहां लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32 प्रतिशत है।
- भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोज़गार के अवसरों से अवगत कराने हेतु महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जा रहे हैं।
- राजकीय विद्यालयों के होनहार विद्यार्थियों के लिए सुपर-100 कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 25 युवाओं ने इस साल जे.ई.ई. परीक्षा में मैरिट में स्थान पाया है और उन्हें आई.आई.टी. में प्रवेश मिला है। इसी प्रकार, 72 युवाओं ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और उन्हें अच्छे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिला है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन की राशि में बढ़ोतरी करते हुए सरकार कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि प्रदान करेगी।

कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक मात्र सुरक्षित उपाय है। लोगों को चाहिए कि वे बिना किसी संकोच के वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवाएं।

सुणो भाइयो, पराली ना जलाइयो

सुण छबीले बोल रसीले

-छबीले तनै वैक्सीन लगवा ली?

-दोनूं लगवा ली। तनै लगवा ली?

-मनैं तो एक बी कोन्या लगवाई सै।

-क्यां तै, जीण तैं छक लिया के? या घर आलां नै फ्री कर राख्या सै?

-अरै टीका लगवाण खातर तीन बै सेंटर पै जा लिया। जिब भी जाऊं सूं, वैक्सीन खत्म होई पावै सै।

-ख्यास करकै लगवाले। तीसरी लहर का रौळा बतावैं सैं। किमे होग्या ना, कनागत काढते हांडैंगे।

-झकोई इतणा माड़ा क्यूं बोलै सै, लगवा ल्यूंगा। न्यू बता, लगवाती हाणा दर्द कितणा अक होवै सै?

-कितो नीं फाळी लांते, एकबै माड़ा सा दर्द होवैगा।

-सुणा सै, लगवाए पाछै ताप भी चढै सै?

-किसे कै चढज्या, किसे कै ना। वैक्सीन लाणिए ताप की गोली भी साथ में देवैं सैं।

-आच्छा न्यू बता, ताप कितणे दिन ताहीं चढै सै? हाम दोनूं बीर-मर्द कट्ठे लगवालें कोई हर्जा तो नहीं?

-लगवाल्यो खसम, लगवाल्यो। इतणै पाछै क्यूकर रहगे? किमे होग्या तै फेर कसूर सरकार का बताओगे। घरआली कै तो इब तैं पहल्यां लगवा लेणी चाहिए थी। उसकै दमे-से की भी शिकायत सै।

-शिकायत के छबीले, कई बै तो कती इंजन-सा बैठज्या सै। दवाई भतेरी दिवा ली। पर कोय खास आराम ना लागता।

-रसीले भाई उसनै धूल, धूमा और धूप तै बचाकै राख्या करो। खैर, रसाई में ईब धूमा तो होता नहीं, सारे काम गैस-चूल्हे पर होज्यां सैं। हारे में बाखर रांधना हो तो यू काम तूं कर लिया कर।

-काम तो हाम रळ-मिलकै करैं सैं छबीले। तनै बेरा सै मैं कदे तासां पै बैठकै टैम खराब नहीं करता। घर में काम ना हो तो डांगरा का कर ल्यूं। डांगरा का ना हो तो खेत कान्या चल्यां जां। रेडियो पै भजन सुण ल्यूं या अखबार पढ़ ल्यूं।

-भाई घरआली का ध्यान राख। वो बी सारे दिन काम में जुटी रहै सै।

-छबीले साल में दो बार उसकी जान नै संकट खड्या होज्या सै। एक बै ईब जब धान कटैंगे और एक बै जब गेहूं कटैंगे। लोग धान की पराली और गेहूंआं के फान्यां में आग ला दे सैं। उसतैं धूमा इतणा होज्या सै अक क्यूकरै भी नहीं बच्या जाता। जिब वातावरण घणा खराब होज्या सै, घरआली का सांस ऊपर का ऊपर और तले का तले रहज्या सै। सांस लेणे में इतणा जोर लागै सै अक आंख्यां में कै पाणी पड़ण लागै सै। कई बै तो हालत इतणी खराब होज्या सै अक देखी नहीं जाती। डाक्टर कै ले जाणी पड़ै सै।

-माड़ी बात सै रसीले।

-माड़ी नहीं छबीले, पाछले सीजन में तो 15 दिन ताहीं अस्पताल में राखणी पड़ी थी। जिब वातावरण ठीक ठाक हो लिया तिब जाकै बाहर ल्याए थे। ईब सारी हाणा अस्पताल में क्यूकर जावैं। डाक्टर का मीटर डाक मारण लागज्या सै। भाई यो तो म्हारी ए कहाणी सै। म्हारे जिसे गाम में, गुहांड में, प्रदेश में और इस एनसीआर में कितणे मरीज होंगे जिनकै दमा, टीबी और छाती की बीमारी सैं। सोचकै देख वे इन दिनां में क्यूकर टैम काटै सैं। जिनकी हालत घणी खराब होज्या वे चालते भी बणैं सैं। भाई, बेरा ना किसी हवा चालगी, किसे कै रहम ए कोन्या।

-रसीले भाई हाम तो पराली ना जलाते, पर किस-किसनै समझावै। किसे नै टोकैं तो सिर पै आवैं। सरकार तो भतेरा जोर देण लागरी सै। पहली बात तो धान की बजाय और फसल लाण पै छह हजार दे, लगा लिये तो पराली निपटाण खातर मशीन देवै, एजेंसियों की मार्फत पराली की खरीद करावै। पराली नै कामयाब करण खातर जगहां-जगहां प्लांट लगा दिए। और सारी बात छोडो, घणी पराली हो तो बेचद्यो और थोड़ी हो तो डांगरां खातर राखकै उसनै खेत में बहाद्यो। माटी में रळज्यागी तो आगली फसल में घणे खाद की भी जरुरत कोन्या पड़ैगी।

- छबीले, मैं हाथ जोड़कै सबतै कहूं सूं- भाइयो, पराली ना जलाइयो।

-मनोज प्रभाकर

सांझी चाल्ली सांझ नै, गेल बसंता पूत

नवरात्र आते ही लड़कियां गांवों में घरों की दीवारों में सांझी बनाने की परंपरा में जुट जाती हैं। सब ओर आस्था व भक्ति का माहौल होता है। कुंवारी लड़कियां गोबर, मिट्टी व प्राकृतिक रंगों से सांझी बनाती हैं। सुबह-शाम सांझी माता की पूजा की जाती है और भोग लगाया जाता है। स्कूलों व कॉलेजों, कला एवं सास्कृतिक कला विभाग, हरियाणा द्वारा लुप्त हो रही सांझी कला के लिए सांझी कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हालांकि समय के साथ सांझी के रंगों व फार्म में बदलाव आने लगा है। इसके बावजूद कलाकृति पारंपरिक ही है और युवा कलाकार प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर इस परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। आश्विन मास के शुक्ला प्रथमा से दशमी तक सांझी की पूजा होती है। दस दिन नवैद्य आदि से बालिकाएं इसकी पूजा करती हैं। विजयदशमी के दिन इसका समापनोत्सव मनाया जाता है और सांझी को उतार कर निकट स्थित किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

कला एवं सास्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा के प्रधान सचिव डी.सुरेश एवं निदेशक प्रतिमा चौधरी का कहना है कि सांझी हरियाणा की लोक पारंपरिक कला है। विरासत निरंतर हरियाणा की लोक कलाओं एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। लोक कला एवं संस्कृति को बचाने की मुहिम में अमृत महोत्सव आयोजन के तहत राज्य स्तरीय सांझी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कला में आया निखार

शाहबाद तहसील के मामूमाजरा गांव की कलाकार रमनदीप कई बार सांझी उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार जीत चुकी है। उनका कहना है कि सांझी कला में चलचित्र पहले की तरह ही बनते हैं, मात्र तकनीक व रंगों में बदलाव आया है। उनका कहना है कि सांझी कला हमारी आस्था व धर्म से जुड़ी है और इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस कला से रूबरू करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसमें दुर्गा मां, पार्वती, चांद, सितारे, आभूषण, सखियां, भाई, चोर, तोता, मोर, पंखें व अन्य आकृतियां बनाई जाती है। उनका कहना है कि पहले मां-दादी गोबर, मिट्टी व प्राकृतिक रंग का ही प्रयोग करती थी, लेकिन अब प्राकृतिक रंग के साथ-साथ एक्रेलिक, पेस्टल रंगों का भी प्रयाग होता है। रमनदीप ने बताया कि वह सांझी को पारंपरिक तरीके से पहले दीवार पर मिट्टी का लेप लगाकर बनाती हैं और उसके बाद गोबर, रंग व अन्य चीजों के प्रयोग करके कलात्मक ढंग से सांझी को रूप देती हैं।

फरीदाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षका कुसुमलता गत पांच सालों से सांझी कला को बढ़ावा दे रही हैं और उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों को भी इस कला में निपुण किया।

लोकगीतों में सांझी

हरियाणवीं लोक में सांझी के आकृतिक, अनुष्ठानिक एवं ऐतिहासिक पक्ष का विशेष महत्व है। लोकजीवन में सांझी को लेकर अनेक तरह की अवधारणाएं हैं। इसे किसान की बेटी के रूप में भी दखा जाता है, जब इसे सामुहिक रूप से विदा किया जाता है तो यह साझली अथवा सांझी कहलाई। लोकगीतों में कहा भी गया है कि.. सांझी चाल्ली सांझ नै, गेल बसंता पूत, साधू हर भी चाल पड़े कमर बांध कै सूत। इसके अतिरिक्त एक अवधारणा इसे दिल्ली की बेटी के रूप में देखने को मिलती है, जबकि राजस्थानी गीतों में बाड़मेर की बेटी के रूप में अवधारणा का प्रचलन है। लोकजीवन में एक अवधारणा पार्वती द्वारा शिव को प्राप्त करने से भी जुड़ी हुई है।

-संगीता शर्मा

हरियाणवी संस्कृति की झलक

कुरुक्षेत्र के विरासत हेरिटेज विलेज में हरियाणा सांझी उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के अलग-अलग जिलों की 54 से अधिक टीमों ने भाग लिया। इसमें हरियाणा की लोककला सांझी के साथ-साथ हरियाणा की प्राचीन विषय-वस्तुओं की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। महिलाएं टोकरी में सांझी का साजो-समान व कलाकृतियां लेकर आईं। फाइन आर्ट्स की लड़कियां भी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और अपनी विरासत के प्रति रूचि को दर्शाया रही थी।

सांझी उत्सव में हरियाणवी लोकनृत्य, रीति-रिवाज, लोक परंपराएं तथा संपूर्ण हरियाणा की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। उत्सव में कुरुक्षेत्र तथा आस-पास के गांव से सुमन, ऋतु, रमनदीप, अमृता, रेनू, स्मृति, बबली देवी, पलक, कविता कश्यप, कृष्णा देवी, ज्योति आर्या, सोनम, सपना देवी, सरस्वती, निर्मला देवी, लभो देवी, नीलम तथा करनाल से सिमरन, अंजू शर्मा, मंजू शर्मा, रवीना, सिमरनजीत कौर, किरण पूनिया, मुकेश रानी, संध्या, आरती ने भाग लिया। इसके अलावा अंबाला से अन्नू, फरीदाबाद से सूरज देवी, कैथल से चंदो देवी व बबली ने भी सांझी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com